

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

धार्यकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. २०]

नई दिल्ली, शनिवार, मई १७, १९८०/वैशाख २७, १९०२

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1980/VAISAKHA 27, 1902

B/16 M → 2322

P.C. → 800

1/M → 10

P.M. → 790

10.6.5

इस पात्र में मिल पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—बाण ३—उप-बाण (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

पूरा कर दिया गया है

(राजा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (लंघ राष्ट्र क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और भारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, २ मई, १९८०

सं. २० का० नं. ५४.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, १९६८ (१९६८ का ५०) की धारा २२ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, १९६९ में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, १९८० है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, १९६९ में,—  
(1) नियम ३ के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
(1) बल में निम्नलिखित चार शाखाएं होंगी, अर्थात् :  
(1) कार्यपालक शाखा ;  
(2) अग्नि-सेवा शाखा ;  
(3) अनुसंचिकीय शाखा; और  
(4) कार्यपालक (महिला) शाखा ;”
- (2) नियम १५ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :  
“(16) काडर.—नियम ३ में विभिन्न चार शाखाओं में से प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठता, प्रोक्षण और पुष्टि के प्रयोजन के लिये अलग काडर होगा।”
3. उक्त नियमों की अनुसूची १ में,—

(i) अनुचर पद के साथै, स्तम्भ ११ की विद्यमान मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(ii) पुनर्नियोजन :—सेना, नौ सेना, वायु सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे निवृत्त/निर्मुक्त कार्मिक, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुचर के पद के समतुल्य पद धारण कर चुके हों, और जो निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों :

(क) व्यायु : ४० वर्ष से कम;

(ख) स्वास्थ्य मानक : भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्वास्थ्य प्रवर्ग “क” अन्य व्यक्तियों के लिये भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिये विहित मानक के समतुल्य;

(ग) चरित्र : बहुत अच्छा-या आदर्श स्वरूप;

(घ) सेवा में व्यवधान : तीन वर्ष से अधिक नहीं।”

(2) सुरक्षा गारद के पद के साथै,—

(1) (i) स्तम्भ ६ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

“१८ वर्ष से अन्यून और २५ वर्ष से अनधिक (विभागीय अध्यक्षियों की दशा में ३५ वर्ष तक शिखिल की जा सकेगी) ;”

(ii) स्तम्भ ७ में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण ३: महिलाओं के लिये शारीरिक मानक वही होंगे जो पुरुषों के लिये हैं, सिवाएं इसके कि

Attest

N. L. N.

मिनिस्टर ऑफ़ इन्डस्ट्रीज  
राजस्मृति, राजस्मृति विभाग  
दिल्ली, दिल्ली ११० ०२१ ११/११

8

9

10

11

12

13

in their respective grades.  
Transfer or Transfer on deputation :  
From amongst persons holding analogous posts in the Headquarters establishment of the Department of Tourism or the Indian Audit Accounts Department or Departmentalised Accounts scheme or Upper Division Clerks with 5 years' regular service in the grade in these Departments. (the period of deputation ordinarily not exceeding three years).

(looking after Administration) in the Regional Tourist Office—Member.  
(d) Director, Government of India Tourist Office, Calcutta, Madras as the case may be.

(NOTE :—One of the members of the Departmental Promotion Committee will preferably be a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Community).

[No. A-12018(1)/78-Admn.I (Tourism)]  
BANU RAM AGGARWAL, Dy. Secy.

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1980

सा० का० नि० 362 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुका द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अवश्यित्—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियमावली, 1980 कहा जा सकेगा।

(2) वे नियम 15 जून, 1978 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 की अनुसूची 7 में, "पदनाम" के बजाय "प्रधान सूचना अधिकारी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अवश्यित्—

"तथापि, इन पद को 15 जून, 1978 से अधिक से अधिक चार वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा से अस्थायी रूप से अलग कर दिया जाएगा"

व्याख्यातक जापन यह संशोधन प्रधान सूचना अधिकारी, पर सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के पद को 15 जून, 1978 से अधिक से अधिक चार वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा से अलग करने के सरकार के नियम के परिणामस्वरूप है। नियम के भूत प्रभावों होने के कारण केन्द्रीय सूचना सेवा के किसी भी अधिकारी का हित प्रभावित नहीं होगा।

[फाइल संख्या ए०-42012/4/78 सी० आई० एस० संशोधन संख्या 76]  
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 1980

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Information Service (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of June, 1978.

2. In Schedule VII to the Central Information Service Rules, 1959, after the words : "Principal Information Officer" under the column "Designation of post", the following words shall be added, namely :

"This post shall, however, be temporarily excluded from the Central Information Service for a period not exceeding four years with effect from 15th June, 1978."

**Explanatory Memorandum :** This amendment is consequential to the decision of the Government to exclude the post of Principal Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi from Central Information Service Rules, 1959 for a period not exceeding four years with effect from 15th June, 1978. This does not affect the interest of any of the Central Information Service officers by reasons of the retrospective operation of the rule.

[F. No. A-42012/4/78-CIS—Amendment No. 76]  
M. L. TANDON, Under Secy.

### अम मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1980

सा० का० नि० 363 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी अधिकारी निधि और प्रकोष्ठ उपर्युक्त अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की द्वारा 1 की उपधारा (3) के बाण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीस या उससे अधिक अवित्तियों को नियोजित करने वाली क्वार्टजाइट खानों को ऐसे वर्ग के खालीनों के रूप में विनियिष्ट करते हैं जिन्हें उक्त अधिनियम 31 मई, 1980 से लागू होगा।

[ए० 35016 (6)/77 ए० एफ० 2]

### MNISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th May, 1980

✓ G.S.R. 563.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees'

*Attested.*

*N. S. Agarwal*  
मनोज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल,  
अधिकारी हाईस, दिल्ली-54

20/11/12

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies quartzite mines, employing twenty or more persons as the class of establishments to which the said Act shall apply with effect from the 31st May, 1980.

[S. 35016(6)77-PF.II]

सा० का० नि० 564.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन हीरा कटाई के उद्योग, अर्थात् हीरा कटाई में लगे हुए किसी उद्योग के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि स्कीम बनाई जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) को धारा 4 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को 31 मई, 1980 से उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है।

[सा० एस० 35016(4)/79 पी० एफ० 2 (i)]

*G.S.R. 564.*—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) in respect of the employees of the Diamond Cutting Industry, that is to say, any industry engaged in the cutting of Diamond;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 31st May, 1980 the said industry to Schedule I to the said Act.

[No. S-35016(4)/79-PFII(i)]

सा० का० नि० 565.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले, सभी अन्तर्राजीय जल-परिवहन स्थापनों को ऐसे बर्मं के स्थापनों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम के उपबंध तारीख 31 मई, 1980 से लागू होंगे।

[सा० एस० 35016 (2) 76 पी० एफ०-ii]  
हंसराज छहबा, उप सचिव

*G.S.R. 565.*—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies all inland water transport establishments and employing twenty or more persons as a class of establishment to which the provisions of the said Act shall apply with effect from the 31st May, 1980.

[No. S-35016(2)/76-PF-II]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 1980

सा० का० नि० 566.—केन्द्रीय अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन अधिनियम और सेवा-शर्त) अधिनियम 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठिपय नियमों का, जो केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के

राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंतप्रधान दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विविध शर्त) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. परिमाणांक.—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विविध शर्त) अधिनियम, 1979 अभिप्रेत है;

(ख) "अपील अधिकारी" से भारत सरकार द्वारा धारा 11 के अधीन नामिनिष्ठ अपील अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "उपमुक्त श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्रलूप" से इन अधिनियमों से संलग्न प्रलूप अभिप्रेत है;

(ङ) "निरीक्षक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक अभिप्रेत है;

(च) "अनुशासन अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त अनुशासन अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "प्रवासी कर्मकार" से धारा 2 में परिभावित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित प्राधिकारी" से ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 12 और धारा 16 के प्रयोजनों के लिए विहित किया जाए; और

(ट) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही शब्द होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

### अध्याय 2

3. स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रोति.—(1) किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रलूप 1 में तीन प्रतियों में उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकरण किया जाने वाला स्थापन स्थित है।

(2) आवेदन के साथ कास किया गया मांग ड्राफ्ट होगा जिसमें स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदेश दिया जाएगा।

(3) आवेदन या तो व्यक्तित रूप से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा या उसे रजिस्ट्रीड डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख उस पर नोट करने के पश्चात् आवेदक को रसीद देगा।

Attested *[Signature]*

प्रधानमंत्री  
प्रधानमंत्री का द्वारा दिया गया दस्तावेज़

प्रधानमंत्री का द्वारा दिया गया दस्तावेज़

21/11/12